भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1826

उत्तर देने की तारीख : 02.03.2020

तमिलनाडु में केन्द्रीय विद्यालय

†1826. सुश्री एस जोतिमणिः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु के संपूर्ण करूर जिले में केवी की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा करूर में स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में प्रचालित और निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित केवी की राज्य-वार सूची क्या है; और

(च) पब्लिक स्कूलों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : केन्द्रीय विद्यालय (केवि) मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों सहित स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का समान कार्यक्रम प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है, यदि वह मंत्रालय अथवा भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित हो, जिसमें नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता के साथ-साथ सरकार का

आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध हो। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती पद्धति" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है उन्हें करूर संसदीय क्षेत्र और साथ ही करूर जिले में नया केवी खोलने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना-समग्र शिक्षा की शुरूआत की है जिसमें तत्कालीन तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) को 01 अप्रैल, 2018 से एक साथ मिला दिया गया है। समग्र शिक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न अंतक्षेपों जैसे स्कूलों का उन्नयन, मौजूदा स्कूलों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और अनुकूल शिक्षण परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का प्रावधान है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा संस्थाओं में महत्वपूर्ण अवसंरचना निर्माण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने हेतु 31.5.2017 को उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) की स्थापना की है। केंद्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान घटक के तहत 2 करोड़ रू. की इकाई लागत और चयनित स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए 5 करोड़ की इकाई लागत के साथ गवर्मेंट आर्ट कॉलेज थंथोनीमलई, करूर के लिए निधि स्वीकृत की है।

(ड.) : आज की तारीख में, विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी अवसंरचना में 283 केवी चल रहे हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण सलंग्न है।

(च) : केंद्र सरकार ने पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ताक सुधारने और दक्षता संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहल की हैं:

i. सक्षमताओं को सुनिश्चित करने पर फोकस करने के लिए, कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों से संबंधित संदर्भ को शामिल करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 की केंद्रीय नियमावली को संशोधित किया गया है, जिसे तदनुसार अंतिम रूप दे दिया गया और राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

ii. शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने जिला स्तर पर अधिगम परिणामों के अंतरालों की पहचान करने और उन अंतरालों को दूर करने हेतु कार्यनीति तैयार करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समर्थ बनाने हेतु 13 नवम्बन, 2017 को कक्षा III, V और VIII के अधिगम परिणामों पर आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया है। इसी प्रकार, कक्षा X के लिए एनएएस का आयोजन 5 फरवरी, 2018 को किया गया था।

iii. समग्र शिक्षा के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्येक्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और स्कूलों में अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए धन दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्य उपाय जैसे सेवारत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान, आईसीटी और डिजिटल पहल, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, आदि शामिल हैं।

iv. ऑनलाइन डी.एलएड पाठ्यक्रम दिनांक 3 अक्टूबर 2017 से शुरू किया गया था और 9,58,513 शिक्षकों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

v. शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए चार वर्षीय बी.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 को आधिकारिक गजट में विनियम प्रकाशित किए गए और दिनांक 3 जून, 2019 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए।

vi. वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में भाग लेने का निर्णय लिया है, जो कि क्षमता आधारित आकलन है।

vii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ग्रेड निर्धारित करने के लिए 70 संकेतकों पर आधारित कार्य-निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) बनाया है।

viii. वर्ष 2019-20 में, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लगभग 42 लाख शिक्षकों और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने सहित महत्वपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने, रचनात्मकता, साथ ही सामाजिक-व्यक्तिगत गुण जैसे सहयोग, टीम-वर्क आदि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, ताकि कक्षाओं को सीखने के अनुकूल बनाया जा सके और बच्चों की दक्षता में सुधार किया जा सके।

****

अनुलग्नक

'तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस जोतिमणि द्वारा लोक सभा में दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1826 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

25.2.2020 तक अस्थायी भवनों में कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अस्थायी भवन के साथ केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	6
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	6
4	बिहार	17
5	छत्तीसगढ़	8
6	दिल्ली	5
7	दादर और नगर हवेली	1
8	दीव	1
9	गुजरात	3
10	हरियाणा	10
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू और कश्मीर	18
13	झारखंड	14
14	कर्नाटक	11
15	केरल	8
	लद्दाख	1
16	लक्षद्वीप	1
17	मध्य प्रदेश	23
18	महाराष्ट्र	5
19	मणिपुर	7
20	मिजोरम	2
21	नगालैंड	3
22	ओडिशा	21
23	पुद्दुचेरी	2

24	पंजाब	12
25	राजस्थान	18
26	तमिलनाडु	4
27	तेलंगाना	9
28	त्रिपुरा	3
29	उत्तर प्रदेश	23
30	उत्तराखंड	13
31	पश्चिम बंगाल	12
कुल		**283**

*****